

औद्योगिक भूमिके नबिंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बहिर सरकार ने राज्य में ज़मीन की लागत कम करने के लिये एक बड़ा फैसला लेते हुए औद्योगिक भूमिके लिये नबिंधन और स्टांप शुल्क को पूरी तरह माफ करने की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों के लिये सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराने की दशा में यह फैसला लिया गया है।
- मद्य नषिध उत्पाद और नबिंधन वभिग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बहिर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA) को सरकार द्वारा आवंटित भूमिके नबिंधन पर स्टांप और नबिंधन शुल्क नहीं देना होगा।
- इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधकिरण के अंदर या बाहर की ऐसी कोई भी ज़मीन, जसिका इस्तेमाल नजिी नविशकों के द्वारा उद्योग स्थापति करने के लिये होगा, उसके दस्तावेज़ों के नबिंधन पर स्टांप शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
- सरकार के इस नरिणय का लाभ केवल नई इकाइयों को ही मलिया, साथ ही नजिी नविशकों को 100 फीसदी रजिस्ट्री और स्टांप फीस में छूट का फायदा तभी मलिया, जब उनके इन्वेस्ट प्रपोजल को राज्य नविश प्रोत्साहन परिषद (SIPB) के स्टेज-1 से क्लीयरेंस मली हो।
- नजिी नविशकों को छूट का फायदा केवल पहले ट्रांजेक्शन में लीज, बकिरी या ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स पर ही मलिया। इसके अलावा अगर नविशक प्रदेश सरकार के तय नयिों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखेगा तो दी गई छूट की राशिकी वसूली उद्योग वभिग नविशक से करेगा।